

कल, जब से पंजाब में विरोध प्रदर्शन के कारण एक फ्लाईओवर पर फंसे पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले की सुरक्षा चूक हुई है। तब से इस बात को लेकर आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं। जिसमें केंद्र का गृह मंत्रालय राज्य सरकार पर आरोप लगा रहा है, वहीं राज्य सरकार केंद्रीय जांच एजेंसी और एसपीजी के ऊपर दोष मढ़ रही है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सुरक्षा योजना में क्या जाता है? कौन सी एजेंसियां शामिल हैं, और अगर योजना में कोई बदलाव होता है तो क्या होता है?’

## कैसे होती है पीएम की सुरक्षा की प्लानिंग?

किसी भी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा की योजना बनाना एक विस्तृत अभ्यास है जिसमें केंद्रीय एजेंसियां और राज्य पुलिस बल शामिल होते हैं। एसपीजी की ब्लू बुक में व्यापक दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। किसी भी नियोजित यात्रा से तीन दिन पहले, एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप), जो पीएम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, एक अनिवार्य एडवांस सिक्क्योरिटी संपर्क (एएसएल) रखता है, जिसमें संबंधित राज्य, राज्य पुलिस में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों सहित संबंधित जिला मजिस्ट्रेट सभी लोग शामिल होते हैं। हर मिनट के विवरण पर चर्चा की जाती है। बैठक खत्म होने के बाद एएसएल रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके आधार पर सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाते हैं।

## बैठक के दौरान क्या तैयार किया जाता है?

आम तौर पर, एक पीएम की यात्रा में पहले अंतिम विवरण को तैयार किया जाता है और फिर उसी के अनुसार यात्रा कार्यक्रम के होने की उम्मीद की जाती है। बैठक में इस बात पर चर्चा की जाती है कि प्रधानमंत्री कैसे पहुंचेंगे (हवाई, सड़क या रेल मार्ग से) और, एक बार जब वह लैंड करेंगे, तो वे अपने कार्यक्रम स्थल (आमतौर पर हेलीकॉप्टर या सड़क मार्ग से) तक कैसे पहुंचेंगे। केंद्रीय एजेंसियों और स्थानीय खुफिया सूचनाओं को ध्यान में रखा जाता है।

आयोजन स्थल की सुरक्षा- जिसमें प्रवेश और निकास, कार्यक्रम स्थल पर आने वालों की तलाशी और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाने जैसे पहलू शामिल हैं - पर चर्चा की जाती है। यहां तक कि मंच की संरचनात्मक स्थिरता की भी जांच की जाती है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कई यात्राओं की सुरक्षा का प्रबंधन किया है, के अनुसार “स्थल की अग्नि सुरक्षा का भी ऑडिट किया जाता है। यहाँ तक कि दिन के लिए मौसम की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा जाता है। यदि किसी परिस्थिति में पीएम के नाव लेने की संभावना है, तो एक नाव की कार्यात्मक तत्परता और सुरक्षा को प्रमाणित किया जाता है। यदि प्रधानमंत्री के जिस मार्ग पर जाने की संभावना है, उस पर झाड़ियां हैं, तो एसपीजी उन्हें काटने के लिए कह सकती है। मार्ग के संकीर्ण हिस्सों की मैपिंग की जाती है और मार्ग की सुरक्षा के लिए और अधिक सुरक्षा बलों को वहां तैनात करने के लिए कहा जाता है।”

यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह, जिन्होंने पहले एसपीजी में सेवा की थी ने बताया “एसपीजी केवल निकटवर्ती सुरक्षा देता है। जब पीएम किसी भी राज्य की यात्रा कर रहे होते हैं, तो समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य पुलिस की होती है। उनके पास खुफिया जानकारी जुटाने, मार्ग की मंजूरी, स्थल की सफाई और भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी है”।

किसी भी खतरे के बारे में इनपुट प्रदान करने के लिए केंद्रीय खुफिया एजेंसियां जिम्मेदार हैं। हालांकि, सुरक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए, इस पर अंतिम फैसला एसपीजी ही करते हैं। सूत्रों ने कहा कि एसपीजी कभी भी पीएम के मूवमेंट की अनुमति तब तक नहीं देती जब तक कि स्थानीय पुलिस आगे बढ़ने का क्लियरेंस नहीं दे देती।

राज्य पुलिस को भी तोड़फोड़ विरोधी जाँच करनी चाहिए और न केवल सुरक्षा कर्मियों को सड़कों पर बल्कि छतों पर स्नाइपर्स को रखकर मार्ग को सुरक्षित करना चाहिए। राज्य पुलिस एक पायलट भी प्रदान करती है जो पीएम के काफिले का नेतृत्व करता है। यदि उनके किसी स्थान पर रुकने या रहने की संभावना है, तो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक एसपी स्तर के अधिकारी को कैंप कमांडेंट के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

जनसभाओं, रैलियों और रोड शो के दौरान पुलिसकर्मियों के अलावा एक एसपी को सुरक्षा के लिए सादे कपड़ों में सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने के लिए तैनात किया जाता है। “रैलियों के दौरान, नेता वर्दीधारी पुरुषों से घिरे नहीं रहना चाहते। लेकिन उन्हें ऐसे छोड़ा भी नहीं जा सकता है। इसलिए सादे कपड़ों में, कभी-कभी पार्टी कार्यकर्ताओं के रूप में भी सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

### अगर योजना में अचानक बदलाव आए तो क्या होगा?

एक आकस्मिक योजना हमेशा पहले से बनाई जाती है। इसीलिए मौसम की रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाता है। “क्या होगा अगर खराब मौसम के कारण, पीएम कार्यक्रम स्थल के लिए उड़ान नहीं भर सकते। इसलिए सड़क मार्ग से एक वैकल्पिक मार्ग की योजना पहले से बनाई जाती है, मार्ग को साफ किया जाता है और सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, भले ही पीएम उड़ान ही क्यों न भरने वाले हों। आप अंतिम समय में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते।

### किसकी क्या-क्या जिम्मेदारी होती है?

ऐसा अक्सर होता है क्योंकि एक हेलीकॉप्टर को 1,000 मीटर दृश्यता की आवश्यकता होती है। “कई बार सर्दियों के दौरान, पीएम को कोहरे के कारण सड़क पर उतरना पड़ता है। उन मार्गों की योजना बनाई गई है और उन्हें पहले से सुरक्षित कर लिया गया है। यदि किसी कारण से मार्ग स्पष्ट नहीं पाया जाता है, तो राज्य पुलिस इसकी अनुमति नहीं देती है और यात्रा रद्द कर दी जाती है।

### यदि स्वतःस्फूर्त विरोध हो तो क्या करें?

विरोध प्रदर्शन हमेशा किसी भी वीआईपी की यात्रा के लिए खतरा होता है और इस प्रकार राज्य पुलिस द्वारा उन्हें विफल करने के लिए पहले से विस्तृत योजना बनाई जाती है। आमतौर पर, स्थानीय खुफिया जानकारी के पास ऐसे इनपुट होते हैं जिन पर समूह विरोध की योजना बना रहे होते हैं और निवारक कार्रवाई की जाती है। “स्थानीय पुलिस के पास संदिग्ध लोगों या संभावित प्रदर्शनकारियों की सूची होती है। उन्हें पहले से डिटेन कर दिया जाता है। इस तरह की जानकारी इकट्ठा करने के लिए भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जाती है। अगर कोई योजनाबद्ध विरोध होता है जिसे रोका नहीं जा सकता है, तो उस मार्ग से बचा जाता है।

## पंजाब में क्या हुआ था?

पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दावा किया है कि पीएम ने अचानक योजना में बदलाव किया था, गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि पीएम के कार्यक्रम के बारे में पहले ही बता दिया गया था। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "डीजीपी पंजाब पुलिस द्वारा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की पुष्टि के बाद वह सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए आगे बढ़े।"

पूर्व डीजीपी ओपी सिंह को इसमें पंजाब पुलिस की गलती नजर आई। "पंजाब के मामले में, जब पीएम ने खराब मौसम के कारण सड़क मार्ग से यात्रा करना चुना, तो यह स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वह पूरे मार्ग को साफ करे, छतों पर स्नाइपर्स रखें, मार्ग की सुरक्षा के बारे में स्थानीय पुलिस क्लियरेंस देती है।"

वर्तमान मामले में, सिंह ने कहा, पीएम एक फ्लाइओवर के ऊपर 15 मिनट से अधिक समय तक पूरी तरह से बेनकाब रहे। "यह एक रोड क्रॉस-सेक्शन भी नहीं था। इसका सीधा सा मतलब है कि स्थानीय पुलिस फ्लाइओवर के प्रवेश और निकास को सुरक्षित करने में विफल रही। बता दें, पंजाब पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ राज्य है। यह एक गंभीर सुरक्षा चूक थी।"



Committed To Excellence

### संभावित प्रश्न ( प्रारंभिक परीक्षा )

- प्र. प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी ब्लू बुक निम्नलिखित में से किस एजेंसी से जुड़ी होती है?
- ( क ) इंटेलिजेंस ब्यूरो  
( ख ) राँ  
( ग ) एसपीजी  
( घ ) राज्य पुलिस

### Expected Question (Prelims Exams)

- Q. The Blue Book related to the security of the Prime Minister is associated with which of the following agencies?
- (a) Intelligence Bureau  
(b) Raw  
(c) SPG  
(d) State Police

### संभावित प्रश्न ( मुख्य परीक्षा )

- प्र. क्या आपके अनुसार पिछले कुछ वर्षों में केंद्र-राज्य सम्बन्धों में आई कटुता अब राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी दुष्प्रभावित कर रही है? टिप्पणी करें। ( 250 शब्द )
- Q. Do you think that the bitterness in Centre-State relations in the last few years is now affecting issues like national security as well? Comment. (250 Words)

Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।